भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2411

13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषयः भारत-विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ

2411. श्री आदित्य प्रसादः
श्रीमती किरण चौधरीः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री बाबू राम निषादः
श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभाः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे:
श्री नरहरी अमीनः
श्री नारायण कोरागप्पाः
श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत-विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) प्लेटफार्म के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या हैं;

(ख) केन्द्रीय बजट 2026 में भारत-विस्तार प्लेटफॉर्म हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है, साथ ही किन मुख्य घटकों और उद्देश्यों के लिए निधियाँ निर्धारित की गई है;

(ग) इस प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए नियोजित समय-सीमा क्या है तथा प्रारंभिक चरण में लक्षित जिलों, भाषाओं तथा किसानों की श्रेणियों के संदर्भ में सांकेतिक कवरेज क्या है;

(घ) क्या भारत-विस्तार के डिजाइन ढांचे में डेटा गोपनीयता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों की पारदर्शिता और छोटे और सीमांत किसानों के लिए समान पहुंच से संबंधित सुरक्षोपायों को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे सुरक्षोपायों की व्यापक विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ): भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली), एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित उपकरण, की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई है, जिसके लिए कुल 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तदनुसार, भारत सरकार ने भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुंच हेतु आभासी एकीकृत प्रणाली) के चरण-1 को एक राष्ट्रव्यापी, एआई-संचालित, ध्वनि-

प्रधान, बहुभाषी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफार्म के रूप में लॉन्च किया है। इसे एक एकीकृत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफार्म के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसे किसानों को विश्वसनीय, रीयल टाइम और स्थान-विशिष्ट व्यक्तिगत कृषि सलाह प्रदान करने के साथ-साथ संबद्ध कृषि और सहायक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सरकारी डिजिटल इकोसिस्टम्स और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करता है ताकि फसल प्रबंधन, मौसम, बाजार मूल्य, कीट और रोग संबंधी चेतावनियों और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर चरणबद्ध तरीके से व्यक्तिगत जानकारी/सलाह प्रदान की जा सके।

17 फरवरी, 2026 को शुरू किए गए प्रथम चरण में, यह प्लेटफॉर्म हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई माध्यमों से उपलब्ध है, जिनमें एक समर्पित टेलीफोन नंबर (155261), एक वॉइस-बेस्ड एआई चैटबॉट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का वेब पोर्टल और एक डाउनलोड करने योग्य मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं। प्रथम चरण में 10 (दस) प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को एकीकृत किया गया है, जिनमें पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड , पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम-आशा, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, प्रति बूंद अधिक फसल और कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन शामिल हैं। सरकार की अगले 3 महीनों में 4 और भाषाएँ तथा अगले 6 महीनों में 5 और भाषाएँ जोड़ने की योजना है।

छोटे और सीमांत किसानों को इसकी सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, यह प्लेटफॉर्म गैर-स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस-बेस्ड और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम (आई.वी.आर.एस) की सुविधा प्रदान करता है। इसे क्षेत्रीय भाषाओं, राज्य-विशिष्ट कृषि योजनाओं और सूचना एवं विस्तार नेटवर्क के साथ-साथ डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक विस्तारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत-विस्तार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और देश के अन्य आईटी कानूनों के अनुरूप विकसित किया गया है। भारत सरकार मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया (सी.ई.आर.टी.-आई.एन.) के साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार इन सभी आईटी प्रणालियों का समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट करती है और जोखिमों की निगरानी करती है।

******